

चीन के बीआरआई (BRI) नविश में गरिवट

प्रलिमिंस के लयि:

बेल्ट एंड रोड इनशिएटिवि (BRI), बलिड बैक बेटर वर्ल्ड, ब्लू डॉट नेटवर्क, ग्लोबल गेटवे

मेन्स के लयि:

बीआरआई और इसका कषेत्तर, नहितारिथ और परणाम, बीआरआई को प्रतसिंतुलति करने हेतु शुरू की गई पहलें ।

चर्चा में क्यों?

चीन स्थिति थकि टैंक की रपिर्ट के अनुसार, चीन के बहुप्रचारति [बेल्ट एंड रोड इनशिएटिवि \(Belt and Road Initiative- BRI\)](#) परयोजना के नविश में वर्ष 2019 के बाद से 5% की गरिवट आई है ।

- नविश में गरिवट का कारण असफल सौदे और कोवडि-19 महामारी है ।
- अवसंरचना ऋण (Infrastructure Debt) और ऋण चूक (Loan Defaults) हेतु चीन अब अफ्रीका में परयोजनाओं के लयि नकदी नहीं दे रहा है ।



प्रमुख बडि

- BRI के बारे में:
 - यह 2013 में शुरू की गई एक मल्टी-अरब डॉलर की पहल है ।
 - इसका उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य एशिया, [खाड़ी कषेत्तर](#), अफ्रीका और यूरोप को भूमि एवं समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ना है ।
 - इसका उद्देश्य विश्व में बड़ी बुनियादी ढाँचा परयोजनाओं को शुरू करना है जो बदले में चीन के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाएगा ।
 - रेलवे, बंदरगाह, राजमार्ग और अन्य बुनियादी ढाँचे जैसी बीआरआई परयोजनाओं में सहयोग करने के लयि 100 से अधिक देशों ने चीन के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं ।

- वर्ष 2000 से 2020 तक चीन ने अफ्रीकी देशों में 13,000 किलोमीटर से अधिक सड़क और रेलमार्ग, बड़े पैमाने पर 80 से अधिक वदियुत सुवर्धियों के निर्माण में मदद की तथा 130 से अधिक चकितिसा सुवर्धियों, 45 खेल स्थलों व 170 से अधिक स्कूलों को वतितपोषित किया है एवं अफ्रीकी संघ सम्मेलन केंद्र का निर्माण किया।
- **BRI के तहत गतविधियाँ:**
 - इसमें पाँच प्रकार की गतविधियाँ शामिल हैं
 - नीति समन्वय, व्यापार संवर्धन, भौतिक संपर्क, रॅन्मिन्बी (चीन की मुद्रा) का अंतरराष्ट्रीयकरण और पीपल-टू-पीपल संपर्क।
- **BRI के तहत मार्ग:**
 - **न्यू सलिक रोड इकोनॉमिक बेल्ट:** इसमें चीन के उत्तर में व्यापार और निवेश केंद्र शामिल हैं; जसिमें म्याँमार एवं भारत के माध्यम से यूरेशिया तक पहुँच बनाना है।
 - **मैरीटाइम सलिक रोड (MSR):** यह दक्षिण चीन सागर से शुरू होकर भारत-चीन, दक्षिण-पूर्व एशिया की ओर जाती है और फरि हदि महासागर के आसपास अफ्रीका एवं यूरोप तक पहुँचती है।
- **संबंधित चिंताएँ (भारत और वशिव के लिये):**
 - **भारत के सामरिक हितों में बाधा:**
 - **चीन-पाकस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC)** पाकस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) और बलूचस्तान से होकर गुजरता है, दोनों ही क्षेत्र लंबे समय से वदिरोह के केंद्र हैं जहाँ भारत को आतंकवाद एवं सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ता है।
 - CPEC दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों को बाधित करेगा और कश्मीर विवाद मामले में पाकस्तान को वैधता प्रदान करने में सहायक हो सकता है।
 - साथ ही CPEC को अफगानस्तान तक वसितारित करने का प्रयास अफगानस्तान के आर्थिक, सुरक्षा और रणनीतिक साझेदार के रूप में भारत की स्थितिको कमजोर कर सकता है।
 - **उपमहाद्वीप में चीन का सामरिक उदय:** चीन द्वारा **चीन-म्याँमार आर्थिक गलियारा (CMEC)** और CPEC के साथ-साथ **चीन-नेपाल आर्थिक गलियारा (CNEC)** भी वकिसति किया जा रहा है जो तबिबत को नेपाल से जोड़ेगा।
 - परियोजना का समापन बदि गंगा के मैदान की सीमाएँ होंगी।
 - इस प्रकार ये तीन गलियारे भारतीय उपमहाद्वीप में चीन के आर्थिक और रणनीतिक उदय को दर्शाते हैं।
 - **पारदर्शिता की कमी:**
 - बीआरआई समझौतों में पारदर्शिता की कमी और छोटे देशों पर चीन के बढ़ते कर्ज ने वैश्विक चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
 - श्रीलंका द्वारा चीन को हंबनटोटा बंदरगाह 99 वर्ष के पट्टे पर देने के संबंध में बीआरआई के नकारात्मक पक्ष के बारे में चिंता व्यक्त की गई है और छोटे देशों में अरबों डॉलर की लागत वाली प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं पर ज़ोर दिया गया है।
- **बीआरआई के प्रतपिकष में पहल:**
 - **B3W पहल:** G7 देशों ने चीन के BRI का मुकाबला करने के लिये 47वें G7 शखिर सम्मेलन में 'बलिड बैक बेटर वर्ल्ड (B3W) पहल' का प्रस्ताव रखा।
 - इसका उद्देश्य वकिसशील और कम आय वाले देशों में बुनियादी ढाँचे के निवेश घाटे को दूर करना है।
 - **ब्लू डॉट नेटवर्क (BDN):** यह अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा गठित एक बहु-हतिधारक पहल है, जो वैश्विक बुनियादी ढाँचे के वकिस के लिये उच्च गुणवत्ता, वशिवसनीय मानकों को बढ़ावा देने तथा सरकारों, नजि क्षेत्र एवं नागरिक समाज को एक साथ लाने के लिये बनाई गई है।
 - BDN को औपचारिक रूप से नवंबर 2019 में बैंकॉक, थाईलैंड में इंडो-पैसफिक बिज़नेस फोरम में घोषित किया गया था।
 - **ग्लोबल गेटवे:** बीआरआई के साथ प्रतस्पर्धा करने के लिये यूरोपीय संघ ने हाल ही में ग्लोबल गेटवे नामक एक नई बुनियादी ढाँचा वकिस योजना शुरू की।

आगे की राह:

- चीन के BRI का मुकाबला करने के लिये अधिक उन्नत देशों द्वारा **वैकल्पिक परियोजनाएँ शुरू** की जानी चाहिये जो मेज़बान/प्राप्तकर्ता देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रकृत में भी सहभागी हों।
- भारत को अपने बुनियादी ढाँचे के निर्माण और उन्नयन के लिये आवश्यक होने पर **जापान जैसे भागीदारों से मदद लेनी चाहिये** और चीनी नेतृत्व वाले कनेक्टविटी कॉरडोर व बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का विकल्प बनाना चाहिये क्योंकि दक्षिण एशिया और हदि महासागर में अकेले कार्य करने की भारत की क्षमता सीमित है।
- भारत के लिये अपने पड़ोसियों को **वैकल्पिक कनेक्टविटी व्यवस्था प्रदान** करने हेतु इस क्षेत्र में अपने भागीदारों के साथ काम करना महत्वपूर्ण है।
 - वदिश नीतिके प्रभाव को बढ़ाने के लिये कनेक्टविटी को एक उपकरण के रूप में देखा जा रहा है।

स्रोत: बिज़नेस स्टैण्डर्ड

रमना काली मंदिर: बांग्लादेश

प्रलम्बिस के लयि:

रमना काली मंदरि, बांग्लादेश मुकत्तियुद्ध ।

मेन्स के लयि:

लबिरेशन वॉर, भारत-बांग्लादेश संबंघों में बांग्लादेश और भारत की जीत की 50वीं वर्षगाँठ ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति ने रमना, ढाका (बांग्लादेश) में पुनर्नरिमति रमना काली मंदरि का उद्घाटन कयि, जहाँ ऐतहिसकि सुहरावर्दी उद्यान (पूर्व रमना रेस कोर्स) स्थति है ।

- पुनर्नरिमति रमना कालीबाड़ी का उद्घाटन मुकत्तिसंग्राम में बांग्लादेश और भारत की जीत की 50वीं वर्षगाँठ के साथ हुआ, जो दोनों पक्षों के बीच द्वपिक्षीय संबंघों की स्वरण जयंती का भी प्रतीक है ।



प्रमुख बडि

■ प्रचिय:

- मार्च 1971 में [ऑपरेशन सर्चलाइट](#) के दौरान पाकसितानी सेना द्वारा मंदरि को नष्ट कर दयिा गया था और करूर कार्रवाई के कारण नरसंहार हुआ एवं [बांग्लादेश मुकत्तियुद्ध](#) हुआ ।
 - मार्च 1971 में पश्चिमि पाकसितान ने बंगालवासियों के आत्मनरिणय को दबाने के लयि पूर्वी पाकसितान में एक नरसंहार का नेतृत्व कयिा । पूर्वी पाकसितान ने बांग्लादेश में जनवादी गणराज्य की स्थापना हेतु लड़ाई लड़ी और जीत हासलि की । बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में भारत ने महत्त्वपूर्ण भूमकि नभिाई ।
- पाकसितान से मुक्त होने के बाद बांग्लादेश के लोगों द्वारा प्रार्थना करने के लयि साइट पर एक छोटा मंदरि स्थापति कयिा गया ।
- वर्ष 2017 में परसिर के पुनर्नरिमाण की घोषणा उस समय की गई थी, जब तत्कालीन भारतीय वदिश मंत्री ने बारीधारा, ढाका में 15 वकिास परयिोजनाओं का उद्घाटन कयिा ।
- ऐतहिसकि रमना काली मंदरि भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच आध्यात्मकि एवं सांस्कृतकि बंधन का प्रतीक है ।

■ रमना काली मंदरि:

- माना जाता है कि देवी काली को समर्पति इस मंदरि का नरिमाण मुगल काल के दौरान कयिा गया था । इसे 400 साल पुराना माना जाता है, हालाँकि यह बताना मुश्कलि है कि इसे कसि वर्ष बनाया गया था ।
- यह मंदरि एक हट्टि संप्रदाय द्वारा बनाया गया था, लेकिन यह पहचान करना मुश्कलि है कि इसे कसिने बनाया था । हालाँकि ऐसा कहा जाता है कि निश्चिति ही इसे [हरचिरण गरि](#) द्वारा बनाया गया था जो मंदरि में महंत थे ।
- यह एक बहुत बड़ा मंदरि नहीं था और वास्तुकला के मामले में काफी सामान्य था, हालाँकि यह ढाकेश्वरी मंदरि के बाबं बांग्लादेश में दूसरा सबसे पुराना हट्टि मंदरि है ।
- 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मंदरि को तब प्रमुखता मलिी जब प्रसदिध संत माँ आनंदमयी ने अपने आश्रम को परसिर में बनाया ।
 - आनंदमयी को लोकप्रयि रूप से "शाहबाग-एर मा" या शाहबाग की माँ के रूप में संबोधति कयिा जाता था ।

■ मंदरि और युद्ध:

- 27 मार्च, 1971 को पाकसितानी सेना द्वारा मंदरि को नष्ट कर दयिा गया तथा पुजारयिों और भक्तों सहति 85 हडिओं की हत्या कर दी गई ।
- 7 मार्च, 1971 को मंदरि तोड़े जाने से कुछ दिनपहले [बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान](#) ने रमना रेसकोर्स मैदान में अपना ऐतहिसकि भाषण

दिया जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता हेतु संघर्ष के लिये बंगालियों का आह्वान किया था।

- बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान (1920-1975) बांग्लादेश के संस्थापक नेता और देश के पहले प्रधानमंत्री थे।

भारत-बांग्लादेश संबंध



■ सैन्य सहयोग:

- बांग्लादेश सरकार ने अपनी सीमाओं से भारत वरिधी उग्रवादी तत्त्वों को समाप्त करने का कार्य किया है जिसके परिणामस्वरूप भारत-बांग्लादेश सीमा क्षेत्र के सबसे शांतपूर्ण क्षेत्रों में से एक बन गई है।
- इसने भारत को अपनी अधिक विवादास्पद सीमाओं पर सैन्य संसाधनों की बड़े पैमाने पर पुनः तैनाती करने की अनुमति दी है।

■ भूमि सीमा समझौता:

- वर्ष 2015 में बांग्लादेश और भारत ने ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते (Land Boundary Agreement) की पुष्टि कर अपनी सीमाओं से संबंधित मुद्दों को शांतपूर्वक हल करने के क्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की।

■ व्यापार संबंध:

- बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत से बांग्लादेश को किया जाने वाला निर्यात 9.21 बिलियन डॉलर और आयात 1.04 बिलियन डॉलर का था।
- इसके साथ ही भारत ने कई बांग्लादेशी उत्पादों को शुल्क मुक्त पहुँच प्रदान करने की पेशकश भी की है।

■ विकास के क्षेत्र:

- विकास के मोर्चे पर भी दोनों देशों के बीच सहयोग में वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में भारत ने सड़कों, रेलवे, पुलों और बंदरगाहों के निर्माण हेतु बांग्लादेश को 8 बिलियन डॉलर की राशिलाइन ऑफ क्रेडिट (एक प्रकार का ऋण) के रूप में प्रदान की है।

■ बेहतर कनेक्टिविटी: दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी में बहुत अधिक सुधार हुआ है।

- कोलकाता और अगरतला के बीच एक सीधी बस सेवा (ढाका से होते हुए) शुरू होने से दोनों स्थानों के बीच यात्रा के लिये केवल 500 किमी. की दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि चिकेन नेक के माध्यम से यात्रा करने पर 1,650 किमी. की दूरी तय करनी पड़ती है।
- बांग्लादेश अपने मोंगला और चटोग्राम (चटगाँव) बंदरगाह से माल दुलाई की अनुमति देता है, जहाँ से सड़क, रेल और जलमार्ग के माध्यम से माल को अगरतला तक पहुँचाया जाता है।

■ सहयोग के नए क्षेत्र:

- भारत आने वाले पर्यटकों में एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेशी पर्यटकों का है, वर्ष 2017 में पश्चिमी यूरोप से आने वाले पर्यटकों के आँकड़ों को पीछे छोड़ते हुए भारत आने वाले पर्यटकों में से प्रत्येक पाँचवाँ पर्यटक बांग्लादेश से था।
- भारत के अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा रोगियों (इलाज हेतु अन्य देशों से भारत आने वाले मरीज़) में 35% से अधिक हिस्सेदारी बांग्लादेश की है और भारत के राजस्व में 50% से अधिक योगदान चिकित्सा यात्रा का है।

■ हालिया विकास:

- इससे पूर्व वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध, जिसमें बांग्लादेश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बांग्लादेश सशस्त्र बलों (Bangladesh Armed Forces) के 122 सदस्यीय दल ने भारत की 72वीं गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया।

स्रोत: द हिंदू

तमिल साहित्य: संगम काल

प्रलिमिंस के लिये:

संगम काल, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियाँ, थरुमुगुरुप्पडई, पोरुनारुप्पडई, सरिपनारुप्पडई, पेरुम्पनुरुप्पडई, मुल्लुईपट्टु, नेदुनलवदाई, मदुरैक्कनजी, कुरनिजीपट्टु, पट्टनिप्पलई और मलाइपदुकदम।

मेन्स के लिये:

संगम साहित्य के विभिन्न पहलू और ऐतिहासिक ग्रंथों के रूप में उनकी प्रासंगिकता, तमिल साहित्य का इतिहास।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा तोलकाप्पियम (Tolkāppiyam) के हदी अनुवाद और शास्त्रीय तमिल साहित्य की 9 पुस्तकों के कन्नड़ अनुवाद का वमोचन किया गया।

- तमिल साहित्य संगम युग से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम कवियों की सभा (संगम) के नाम पर रखा गया है।

मुख्य बटि

■ संगम काल के बारे में:

- यह लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य की अवधि है। दक्षिण भारत (कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्र) में लगभग तीन सौ ईसा पूर्व से तीन सौ ईसवी के बीच की अवधि को **संगम काल** के नाम से जाना जाता है।
- इसका नाम उस अवधि के दौरान आयोजित संगम अकादमियों/सभाओं के नाम पर रखा गया है जो मदुरै के पांड्य राजाओं के शाही संरक्षण में फली-फूली।
- संगमों में प्रख्यात विद्वान इकट्ठे हुए और सेंसर बोर्ड के रूप में कार्य किया तथा संकलन के रूप में सबसे अच्छे साहित्य का प्रतिपादन किया गया।
- ये साहित्यिक कृतियाँ द्रविड़ साहित्य के शुरुआती नमूने थे।
- संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर तीन राजवंशों- चेरों, चोल और पांड्यों का शासन था।
- **तीन संगम:**
 - तमिल कविदंतियों के अनुसार, प्राचीन दक्षिण भारत में तीन संगमों (तमिल कवियों का समागम) का आयोजन किया गया था, जिसे मुच्यंगम (**Muchchangam**) कहा जाता था।
 - माना जाता है कि **प्रथम संगम मदुरै** में आयोजित किया गया था। इस संगम में देवता और महान संत शामिल थे। इस संगम का कोई साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है।
 - **दूसरा संगम कपाटपुरम्** में आयोजित किया गया था, इस संगम का एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ **तोलकाप्पियम** ही उपलब्ध है।
 - **तीसरा संगम भी मदुरै** में हुआ था। इस संगम के अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो गए थे। इनमें से कुछ सामग्री समूह ग्रंथों या महाकाव्यों के रूप में उपलब्ध है।

■ संगम साहित्य:

- संगम साहित्य में तोलकाप्पियम, एट्टुटोर्गई, पट्टुप्पट्टु, पथिनेकिलकनक्कु ग्रंथ और **शलिप्पादिकारम्** और **मणमिखलै** नामक दो महाकाव्य शामिल हैं।
 - **तोलकाप्पियम:** यह तोलकाप्पियार द्वारा लिखा गया था और इसे तमिल साहित्यिक कृतियों में सबसे पुराना माना जाता है।
 - यह व्याकरण से संबंधित एक ग्रंथ है, साथ ही यह उस समय की राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की जानकारी भी प्रदान करता है।
 - यह नौ खंडों के तीन भागों में व्याकरण और काव्य पर एक अनूठा काम है, जिनमें से प्रत्येक एजुट्टु (अक्षर), कोल (शब्द) और पोरुल (वर्ण वस्तु) से संबंधित है।
 - सामान्य बोलचाल से लेकर काव्यात्मकता तक मानव भाषा के लगभग सभी स्तर तोलकाप्पियार के विश्लेषण के दायरे में आते हैं, क्योंकि वे स्वर विज्ञान, आकृत विज्ञान, वाक्य रचना, बयानबाज़ी, छंद और काव्य पर उत्कृष्ट काव्यात्मक एवं एपिग्रामेटिक बयानों में व्यवहार करते हैं।
 - **एट्टुटोर्गई (आठ संकलन):** इसमें आठ रचनाएँ शामिल हैं- ऐंगुनूरु, नरनाई, अगनौरु, पुराणनूरु, कुरुंतोर्गई, कलत्तिटोर्गई, परपिदल और पदरिट्टु।
 - **पट्टुप्पट्टु (दस रचना):** इसमें दस रचनाएँ शामिल हैं- थरुमुगुरुप्पडई, पोरुनारुप्पडई, सरिपनारुप्पडई, पेरुम्पनुरुप्पडई, मुल्लुईपट्टु, नेदुनलवदाई, मदुरैक्कनजी, कुरनिजीपट्टु, पट्टनिप्पलई और मलाइपदुकदम।
 - **पथिनेकिलकनक्कु (Pathinenkilkanakku):** इसमें नैतिकता और नैतिकता संबंधी अठारह कार्य शामिल हैं।
- इन कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण महान तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर द्वारा लिखित तिरुकुरल है।
- **तमिल महाकाव्य:** शलिप्पादिकारम् 'इलांगोआदगिल' द्वारा और मणमिखलै 'सीतलैसत्तनार' द्वारा लिखे गए महाकाव्य हैं।
 - वे संगम समाज और राज्य व्यवस्था के बारे में बहुमूल्य विवरण भी प्रदान करते हैं।

मॉब लचिगि

प्रलिमिन्स के लिये:

मॉब लचिगि, पूनावाला केस, मॉब लचिगि से संबंधित कानूनी प्रावधान।

मेन्स के लिये:

मॉब लचिगि का कारण और इसे दूर करने के लिये किये गए उपाय।

चर्चा में क्यों?

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ने अमृतसर और कपूरथला में लचिगि की हालिया घटनाओं पर चर्चा व्यक्त की है।

प्रमुख बिंदु:

■ परिचय:

- मॉब लचिगि एक ऐसा शब्द है जिसका **इस्तेमाल लोगों के एक बड़े समूह द्वारा लक्षित हिसा के कृत्यों का वर्णन करने के लिये** किया जाता है।
- भीड़ मानती है कि वह **पीड़ित को गलत कार्य** (ज़रूरी नहीं कि अवैध हो) करने के लिये दंडित कर रही है और किसी कानून का पालन किये बिना कथित आरोपी को दंडित करने हेतु कानून अपने हाथ में लेती है।

■ मॉब लचिगि का कारण:

○ असहषिणता:

- लोग कानून के कृत्यों को स्वीकार करने में असहषिण हैं और कथित व्यक्ति को अनैतिक मानते हुए दंडित करने के लिये आगे बढ़ते हैं।

○ पूर्वाग्रह:

- जाति, वर्ग, धर्म आदि जैसी विभिन्न पहचानों पर आधारित पूर्वाग्रह : मॉब लचिगि एक घृणित अपराध है जो विभिन्न जातियों, लोगों और धर्मों के बीच पूर्वाग्रहों के कारण बढ़ रहा है।

○ गौ हत्या के आरोप में लचिगि:

- यह उन महत्वपूर्ण कारणों में से एक है जो मॉब लचिगि की गतिविधियों में तेज़ी से वृद्धि करता है।

○ शीघ्र न्याय का अभाव:

- न्याय प्रदान करने वाले अधिकारियों का अकुशल कार्य ही प्राथमिक कारण है कि लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं तथा परिणामों से डरते नहीं हैं।

○ पुलिस प्रशासन की अक्षमता:

- पुलिस अधिकारी लोगों के जीवन की रक्षा करने और लोगों के बीच सद्भाव बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लेकिन उनकी अप्रभावी जाँच प्रक्रिया के कारण यह घृणित अपराध दैनिक-दैनिक बढ़ता ही जा रहा है।

■ मॉब लचिगि के प्रकार: कारणों के आधार पर मॉब लचिगि को छह प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- सांप्रदायिक आधारित
- जादू-टोना
- सम्मान की रक्षा हेतु हत्या
- गोजातीय-संबंधी मॉब लचिगि
- बच्चा चोरी का शक
- चोरी के मामले

■ संबंधित मुद्दे:

- मॉब लचिगि मानव गरमा का उल्लंघन है, साथ ही यह संविधान के [अनुच्छेद-21](#) और 'मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा' का भी उल्लंघन है।
- ऐसी घटनाएँ 'समानता के अधिकार और 'भेदभाव के निषेध' संबंधी मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करती हैं, जो भारत के संविधान के [अनुच्छेद-14 और 15](#) में निहित हैं।
- हालाँकि देश के कानून में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है और इसलिये इसे केवल हत्या के रूप में रखा गया है, क्योंकि इसे अभी तक [भारतीय दंड संहिता](#) के तहत शामिल नहीं किया गया है।

■ उठाए गए संबंधित कदम:

○ नविवारक उपाय:

- जुलाई 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने **तहसीन एस. पूनावाला बनाम यूओआई** मामले में लचिगि और भीड़ की हिसा से नपिटने के लयि कई नविवारक, उपचारात्मक और दंडात्मक उपाय नरिधारति कयि थे।
 - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मॉब लचिगि को 'भीड़ तंत्र का एक भयानक कृत्य' कहा।

○ नामति फास्ट ट्रैक कोर्ट:

- राज्यों को हर ज़िले में वशिष रूप से मॉब लचिगि से जुड़े मामलों से नपिटने के लयि नामति फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापति करने का नरिदेश दया गया था।

○ स्पेशल टास्क फोर्स:

- न्यायालय ने नफरत भरे भाषणों, भड़काऊ बयानों और फेक न्यूज़ फैलाने में शामिल लोगों के बारे में खुफिया रपिर्ट हासलि करने के उद्देश्य से एक वशिष टास्क फोर्स के गठन पर भी वचिर कयि था, जसिके कारण मॉब लचिगि हो सकती है।

○ पीड़ति मुआवज़ा योजना:

- पीड़तियों के राहत और पुनरवास हेतु पीड़ति मुआवज़ा योजनाओं (Victim compensation schemes) को स्थापति करने के लयि भी नरिदेश जारी कयि गए।
- एक साल बाद जुलाई 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और कई राज्यों को नोटसि जारी कर कहा कवि उपायों को लागू करने की दशिा में उनके द्वारा उठाए गए कदमों को प्रस्तुत करें और अनुपालन रपिर्ट दाखलि करें।
- अब तक केवल तीन राज्यों मणपुरि, पश्चिमि बंगाल और राजस्थान ने मॉब लचिगि के खलिाफ कानून बनाए हैं।
 - हाल ही में झारखंड वधिानसभा ने 'झारखंड मॉब वायलेंस एंड मॉब लचिगि नविवरण वधिियक 2021 को पारति कयि है।

आगे की राह

- लचिगि एक ऐसी घृणति घटना है जसिका उस लोकतांत्रिकि समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहयि, जसि पर भारत को गर्व है।
- लचिगि की घटना शासन को वशिष रूप से अस्थिर करती है, जबकि भीड़ द्वारा की गई हिसा का कार्य स्वयं कानून प्रवर्तन की वफिलता का संकेत है, यह एक स्पष्ट वचिर के रूप में प्रतबिद्ध होती है जसिमें कानून की सहायता नहीं ली जाती है।
- भीड़ की हिसा के मामलों में पुलिस की नषिक्रयिता सदिधांतों को वकृि रूप से तोड़मरोड़, पुलिस द्वारा न्यायेतर दंड की स्पष्ट सार्वजनिकि स्वीकृतिनि दयि जाने के कारण देखी जाती है।
- यह देश के लयि घातक है। भीड़ की हसिक घटनाओं के कारण वास्तव में देश की बदनामी होती है और इसे समाप्त करने के लयि पुलिस को सख्ती के साथ हस्तक्षेप करना चाहयि।
- भीड़ द्वारा की जाने वाली हसिक कार्यवाहयिों को अनुमतदि देने वाली सामाजिकि सहमतपर सवाल उठाने में राजनीतिकि नेतृत्व की भी भूमिका होती है।

स्रोत: द हट्रि

वरनाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम: नीतिआयोग

प्रलिमिस के लयि:

वरनाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम, अटल इनोवेशन मशिनि, आठवीं अनुसूची

मेन्स के लयि:

वीआईपी और भाषा की बाधाओं को दूर करने तथा इनोवेटर्स को सशक्त बनाने में इसका महत्त्व। भारत में एक नवोन्मेषी पारस्थितिकि तंत्र बनाने में सरकारी प्रयास।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **अटल इनोवेशन मशिनि (AIM)**, नीतिआयोग ने अपनी तरह का पहला वरनाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम (VIP) लॉन्च कयि है, जो देश में नवोन्मेषकों और उद्यमयिों को भारत सरकार की **22 अनुसूचित भाषाओं** में नवाचार इको-ससि्टम तक पहुँच में सक्षम बनाएगा।

प्रमुख बदि

■ परिचय:

- VIP नवाचार और उद्यमति के क्षेत्र में भाषा की बाधा को दूर करने की एक पहल है, यह रचनात्मक अभवियक्तयिों और लेन-देन की

भाषाओं को व्यवस्थिति रूप से अलग कर देगा।

- VIP के लिये आवश्यक क्षमता का निर्माण करने हेतु AIM ने 22 अनुसूचित भाषाओं में से प्रत्येक में एक वर्नाक्युलर टास्क फोर्स (VTF) की पहचान की है और इसमें प्रशिक्षण देगा।
- प्रत्येक टास्क फोर्स में स्थानीय भाषा के शिक्षक, वरिष्ठ विशेषज्ञ, तकनीकी लेखक और क्षेत्रीय अटल इनक्यूबेशन सेंटर (AICs) के नेतृत्व शामिल हैं।

■ महत्त्व

- यह भारतीय नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जो युवा एवं महत्वाकांक्षी लोगों के संज्ञानात्मक और डिज़ाइन दृष्टिकोण को मज़बूत करेगा।
- यह डिज़ाइन विशेषज्ञों और नवाचार करने वाले लोगों के एक मज़बूत स्थानीय नेटवर्क के निर्माण में भारत की सहायता करेगा।
- यह भाषा की बाधाओं को दूर करने और देश के सबसे दूर के क्षेत्रों में नवप्रवर्तनकर्त्ताओं को सशक्त बनाने में मदद करेगा।
- यह उन स्थानीय नवप्रवर्तनकर्त्ताओं के लिये समान अवसर पैदा करेगा, जो भारतीय आबादी के 90% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।
 - वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, केवल 10.4% भारतीय अंग्रेज़ी बोलते हैं, जसमें से अधिकांश लोग इसका प्रयोग अपनी दूसरी, तीसरी या चौथी भाषा के रूप में करते हैं।
 - केवल 0.02% भारतीय अपनी प्राथमिक भाषा के रूप में अंग्रेज़ी बोलते थे।
- किसी की भाषा और संस्कृति में सीखने हेतु पहुँच प्रदान करके AIM स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक नवाचार पाइपलाइनों को समृद्ध करने के लिये तत्पर है।

■ नवाचार/उद्यमिता से संबंधित अन्य पहलें:

- [भारत नवाचार सूचकांक](#)
- [इम्प्रेटि \(अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी को प्रभावित करना\)](#)
- [उच्चतर आविष्कार योजना \(यूएवाई\)](#)
- [स्टार्टअप इंडिया पहल](#)
- [मशिन इनोवेशन 2.0](#)
- [एआईएम-प्राइम](#)
- [AIM-iCREST: नीतिआयोग](#)
- [अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर](#)
- [अटल टकिंग लैब्स](#)

अटल नवाचार मशिन (AIM)

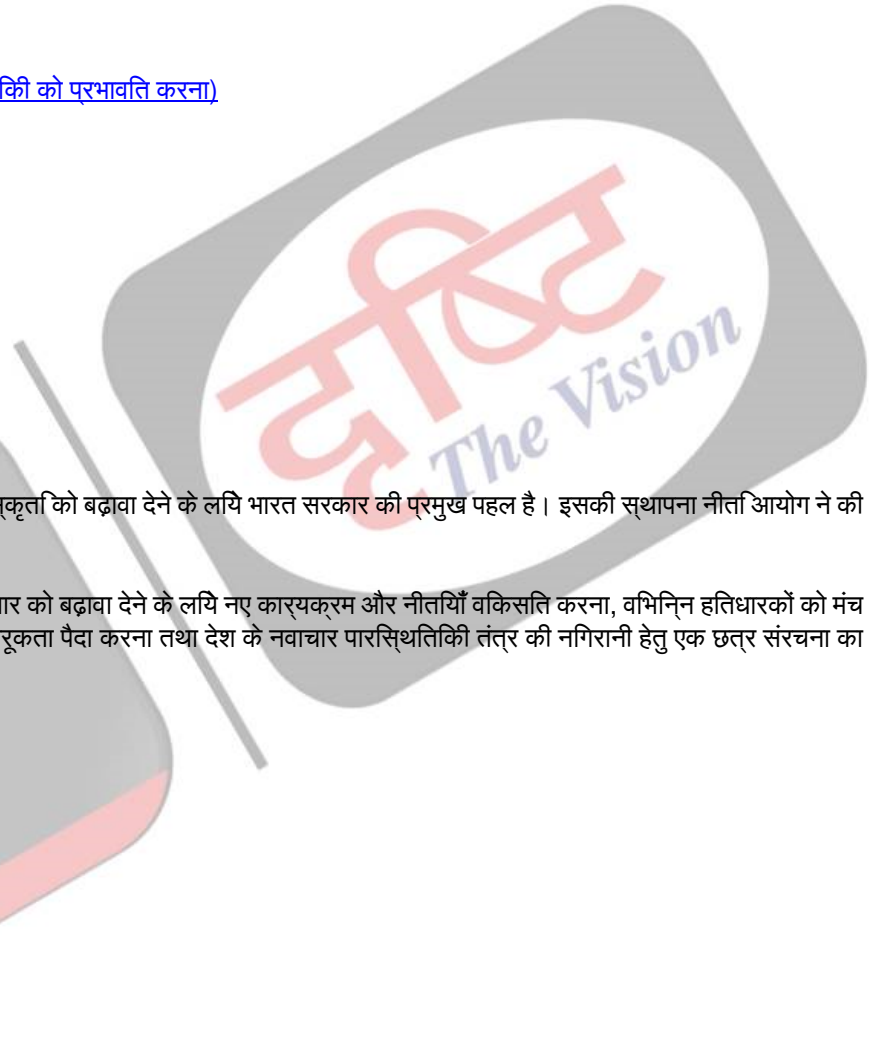
■ अटल नवाचार मशिन के बारे में:

- AIM देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृतिको बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार की प्रमुख पहल है। इसकी स्थापना नीतिआयोग ने की है।

■ उद्देश्य:

- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिये नए कार्यक्रम और नीतियाँ विकसित करना, विभिन्न हतिधारकों को मंच और सहयोग के अवसर प्रदान करना, जागरूकता पैदा करना तथा देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की नगिरानी हेतु एक छत्र संरचना का निर्माण करना।

■ अटल नवाचार मशिन के तहत की गई पहल:





■ प्रमुख सफलता:

- AIM की पहलों के तहत वर्ष 2015 में [वैश्विक नवाचार सूचकांक](#) में भारत 81वें स्थान पर और वर्ष 2020 में 48वें स्थान पर रहा है।

आठवीं अनुसूची

- इस अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के भाग XVII में [अनुच्छेद 343 से 351](#) तक शामिल अनुच्छेद आधिकारिक भाषाओं से संबंधित हैं।
 - हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि किसी भी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिये कोई नश्चित मानदंड निर्धारित नहीं है।
- संविधान की आठवीं अनुसूची में नमिनलखित 22 भाषाएँ शामिल हैं:
 - असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी।
- इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था।
- वर्ष 1967 में संधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था।
- वर्ष 1992 में 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया।
- वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि वर्ष 2004 से प्रभावी हुआ, द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया।

स्रोत: पीआईबी

भारत में मसाला क्षेत्र

प्रलिम्स के लिये:

प्रमुख मसाला उत्पादक राज्य, मसाला क्षेत्र हेतु प्रमुख आँकड़े

मेन्स के लिये:

भारत में मसाला उत्पादन, मसाला क्षेत्र हेतु की गई पहल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने 'स्पाइस स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लान्स 2021' पुस्तक का वमिचन किया है।

- यह पुस्तक देश में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2020-21 तक के पछिले सात वर्षों के दौरान मसालों के उत्पादन में हुई वृद्धि पर प्रकाश डालती है।

प्रमुख बिंदु

■ मसालों के वषिय में:

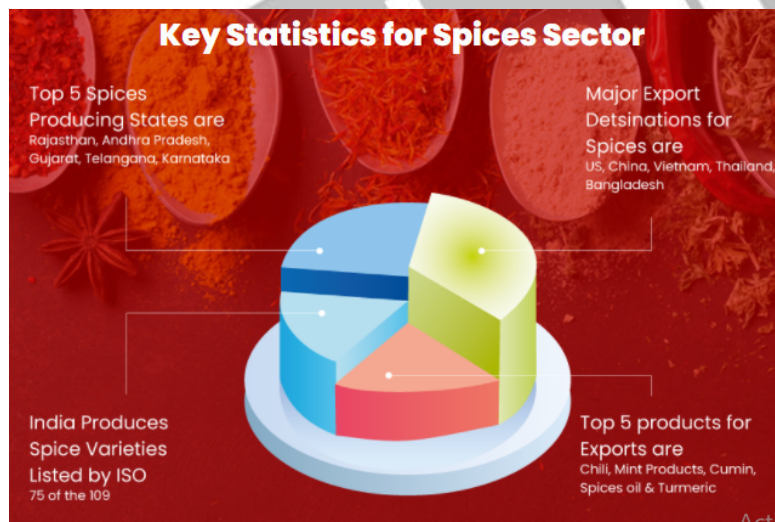
- मसाले बीज, फल, छाल, राइजोम और पौधों के अन्य भागों से प्राप्त सुगंधित खाद्य उत्पाद प्राप्त होते हैं।
- उनका उपयोग भोजन के संरक्षण और दवाओं, रंगों एवं इत्र के रूप में किया जाता है।
- मसालों को हजारों वर्षों से व्यापार की वस्तुओं के रूप में अत्यधिक महत्त्व दिया गया है।
 - **मसाला शब्द लैटिन से आया है, जिसका अर्थ है 'माल'।**
- विशेष रूप से महामारी की अवधि के दौरान मसालों को स्वास्थ्य प्रक के रूप में मान्यता देने के कारण मसालों की मांग में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है।
 - इसे हल्दी, अदरक, जीरा, मरिच आदि जैसे मसालों के बढ़ते नरियात से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

■ भारत में मसाला उत्पादन:

- भारत मसालों का वशिव में सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और नरियातक देश है।
- बदलती जलवायु के कारण उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय से समशीतोष्ण तक लगभग सभी जलवायु के मसालों का भारत में उत्पादन किया जाता है।
- वास्तव में भारत के लगभग सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में किसी-न-किसी मसाले का उत्पादन किया जाता है।
- संसदीय अधिनियम के तहत कुल 52 मसालों को मसाला बोर्ड के दायरे में लाया गया है।
 - मसाला बोर्ड (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) भारतीय मसालों के विकास और वशिव्यापी प्रचार हेतु प्रमुख संगठन है।
 - यह मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 द्वारा स्थापित किया गया था।
- भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जो उन मसालों का उत्पादन करते हैं जिनका राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में बहुत अधिक मूल्य है।
 - सबसे अच्छा उदाहरण **'कश्मीरी केसर'** है जो दुनिया का सबसे अच्छा केसर है।
 - कश्मीरी केसर को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग का दर्जा मिला है।

■ मसाला व्यापार:

- मसालों का नरियात देश में सभी बागवानी फसलों के कुल नरियात आय में 41% का योगदान देता है।
- यह समुद्री उत्पादों, गैर-बासमती चावल और बासमती चावल के बाद कृषिवस्तुओं में चौथे स्थान पर है।



संबंधित सरकारी पहल:

- हाल ही में **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)** ने **कोडेक्स एलमिंटेरियस कमीशन (CAC)** के तहत स्थापित **मसालों और पाक जड़ी बूटियों (CCSCH)** पर कोडेक्स समिति के पाँचवें सत्र का उद्घाटन किया।
- मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति (CCSCH) के बारे में:
 - **स्थापना:** इसका गठन वर्ष 2013 में किया गया था।
 - **संदर्भ शर्तें:**
 - मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों हेतु उनकी सूखी और नरिजलति अवस्था संबंधी वशिव्यापी मानकों को वसित्त करना।
 - मानकों के विकास की प्रक्रिया में दोहराव से बचने के लिये अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ परामर्श करना आवश्यक है।

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/23-12-2021/print>

